DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS- दैनिक जागरण नई दिल्ली, 24 मार्च, 2023 DATED----------

कचरा निस्तारण से सात माह में 15 मीटर कम हुई तीनों लैंडफिल साइट की ऊंचाई

उपराज्यपाल ने गाजीपुर, ओखला और भलस्वा लैंडफिल साइट का किया दौरा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी की सुंदरता पर ग्रहण लगाने वाली गाजीपुर, ओखला और भलस्वा लैंडफिल साइट की ऊंचाई सात महीने में 15 मीटर तक कम हो गई है। सिर्फ छह महीने में पुराने अपशिष्ट निपटान की दर में भी भारी वृद्धि हुई है। अपशिष्ट निपटान की दर, जो जून 2022 में 1.41 लाख मीट्रिक टन प्रतिमाह थी, बढ़कर छह लाख मीट्रिक टन प्रतिमाह हो गई है। केंद्र सरकार की एजेंसियों, उद्योगों और जनभागीदारी के कारण तीन महीने में प्रतिमाह 10 लाख मीट्रिक टन कचरे का निपटान संभव हो सकेगा। वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट और सीमेंट कंपनियों के बाद अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पेपर मिलें भी पहली बार लैंडफिल साइट से ज्वलनशील कचरा उठा रही हैं।

तीनों लैंडफिल साइट पर कचरे के पहाड़ को खत्म करने के लिए चल रहे काम का जायजा लेने के लिए एलजी वीके सक्सेना बृहस्पतिवार को वहां जमा कचरे के निस्तारण (लीगेसी वेस्ट डिस्पोजल) संबंधी प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान

गाजीपुर लैंडफिल साइट का निरीक्षण करते एलजी वीके सक्सेना ● सौ. राजनिवास

अधिकारियों ने उन्हें बताया कि कचरा निस्तारण में तजी से सात माह में तीनों लैंडफिल साइट की ऊंचाई लगभग 15 मीटर तक कम हुई है और इसकी ऊंचाई घटाने की दिशा में गंभीरता से काम किया जा रहा है। यहां तक कि पारंपरिक अपशिष्ट निपटान में 400 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

एलजी ने बताया कि एनएचएआई और डीडीए पहले से ही अपने-अपने निर्माण स्थलों पर 45 लाख मीट्रिक टन अपशिष्ट और सीएंडडी (निर्माण और विध्वंस) कचरे का इस्तेमाल कर रहा है। वहीं, जनभागीदारी के तहत छह महीने में एक लाख मीट्रिक टन अपशिष्ट और सीएंडडी कचरा यहां से उठाया गया है। इसी प्रकार छह महीने के दौरान बने और अपग्रेड किए गए कचरे से बिजली बनाने वाले प्लांटों ने रोज 6,000 मीट्रिक टन ज्वलनशील कचरा यहां से उठाया है।

एक नए प्रयोग के तहत कचरे के निपटान में कारपोरेट जगत को पुराने ज्वलनशील कचरे के निस्तारण में शामिल किया गया था। इसके तहत सीमेंट कंपनियों ने लैंडफिल साइट से प्रत्येक माह 15 से 20 हजार मीट्रिक टन ज्वलनशील कचरा उठाया है, जिसका इस्तेमाल ईंधन के तौर पर किया जा रहा है। अब तक पांच सीमेंट कंपनियां लैंडफिल साइट से यह कचरा उठा रही हैं। इनमें राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की कंपनी भी शामिल है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली, मुजफ्फरनगर, इटावा की पेपर मिलों ने भी प्रतिदिन लगभग 100 मीट्रिक टन ज्वलनशील कचरा उठाना शुरू कर दिया है।

एलजी ने बताया कि बदरपुर में एल एंड डीओ की लगभग 400 एकड़ निचली भूमि पर ओखला लैंडफिल साइट से इनर्ट और सीएंडडी कचरे को लाकर यहां भरने की योजना है। उन्होंने ओखला और भलस्वा लैंडफिल साइट पर हो रहे काम की गति पर संतोष जताया, जहां प्रतिदिन 15,000 मीट्रिक टन कचरे के निपटान का लक्ष्य शीघ्र हासिल कर लिया जाएगा।

फर्जी वेबसाइटों को लेकर डीडीए ने दर्ज कराई शिकायत

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: कुछ जालसाज दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों को बड़ा चूना लगाने की फिराक में हैं। डीडीए ने स्वयं इसकी जानकारी दी है। डीडीए के संज्ञान में आया है कि कुछ जालसाज प्राधिकरण की हाउसिंग स्कीम के नाम पर फर्जी यूआरएल (https://DDAflat.org.in/index.php) का इस्तेमाल कर जनता को फ्लैट बुक करने के लिए लुभा रहे हैं। डीडीए ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) और साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज कराई है।

साथ ही प्राधिकरण ने आम लोगों को भी ऐसी धोखाधड़ी से सचेत किया है। लोगों को आगाह करते हुए डीडीए ने कहा है कि ऐसे किसी भी फर्जीवाड़े से सावधान रहें और इस प्रकार की प्रक्रिया में लिप्त व्यक्तियों और योजनाओं से बचें।

डीडीए ने कहा है कि उसकी सभी आवास योजनाओं के लिए वेबसाइट www.dda.org.in और www.dda.gov.in के माध्यम से ही आनलाइन आवेदन करें। अन्य किसी वेबसाइट व सोर्स के द्वारा लोगों के साथ धोखाधड़ी की जा सकती है। इससे उन्हें वित्तीय हानि हो सकती है। ऐसे में डीडीए ने लोगों से अनुरोध किया है कि डीडीए की आधिकारिक वेबसाइटों के माध्यम से ही नियमित अपडेट प्राप्त करें व ट्रांजेक्शन आदि करें। दिल्ली में आएदिन इस तरह के मामले देखने को मिल रहे हैं जब विभिन्न तरीकों से लोगों को ठगा जा रहा है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPER नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शुक्रवार, 24 मार्च 2023 ATED----------

सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के लोग विकल्पों से नाखुश

लोगों ने कहा-डीडीए को उनकी परेशानी नहीं दिख रही

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

मुखर्जी नगर के सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के लोग डीडीए के तीनों विकल्पों से नाखुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि डीडीए उन्हें पीड़ित की नजर से देखे। लोगों के अनुसार एलजी के निर्देशों के बावजूद भी अब तक डीडीए ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। इमारत में दरार और कंक्रीट के टुकड़ों के गिरने की घटनाएं लोगों को डरा रही हैं। लोगों के अनुसार डीडीए ने सीबीआई की रिपोर्ट में कमियां मानी हैं, लेकिन ज्यादातर कर्मी रिटायर हो चुके हैं। सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के आरडब्ल्यूए अध्यक्ष अमरेंद्र झा के अनुसार विजिलेंस रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई को अधिकारियों, एजेंसियों और लैब सेंटर के खिलाफ एफआईअर करने का आदेश महज लीपापोती करने का तरीक लग रहा है। उन्होंने कहा कि डीडीए सोसायटी के लोगों से हमदर्दी दिखाने की बजाय इस मौके में अपने फायदे के मौके ढूंढ रही है।

उन्होनें बताया कि तीनों विकल्प भ्रामक हैं। बायबैक के तहत डीडीए फ्लैट्स की कीमत का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा देने का प्रस्ताव दे रहा है। लोगों ने यहां री सेल में महंगे फ्लैट्स खरीदकर उनकी फर्निशिंग करवाई है। ऐसे में लोगों को काफी कम रकम मिलेगी। दूसरे विकल्प में डीडीए मुखर्जी नगर के बदले ऐसे फ्लैट्स दे रहा है, जिसे डीडीए बेच ही नहीं पा रहा है। यह दूरदराज के इलाके मसलन नरेला के फ्लैट्स हैं। तीसरे विकल्प में लोग अपने घर खाली करें या सोसायटी डीडीए को सौंप दें और फिर डीडीए यहां जितने मर्जी उतने फ्लैट्स बनाए। डीडीए करीब 180 अतिरिक्त फ्लैट्स बनाने की तैयारी है। लोगों के अनुसार इससे कम जगह में अधिक लोग रहेंगे, ओपन एरिया और ग्रीनरी कम हो जाएगी।

लोगों को रहता है चोटिल होने का खतरा

लोगों का मानना है...

- रीडिवेलपमेंट में ज्यादा फ्लैट बने तो ओपन एरिया हो जाएगा कम
- उनका कहना है कि इमारत में दरार और कंक्रीट के टुकड़े गिरते हैं
- डीडीए करीब 180 अतिरिक्त फ्लैट्स बनाने की तैयारी है

लोग रीडिवेलपमेंट चाहते हैं, एक्स्ट्रा फ्लैट नहीं

आरडब्ल्यूए के अनुसार ज्यादातर लोग रीडिवेलपमेंट चाहते हैं, लेकिन अतिरिक्त फ्लैट नहीं चाहते। साथ ही डीडीए के प्रस्ताव में जो किराया दिया जा रहा है वह काफी कम है। वहीं डीडीए अधिकारी के अनुसार डीडीए के पास अब भी इस कॉम्प्लेक्स के कुछ हिस्से की ऑनरशिप है। ऐसे में प्लान है कि जगह का अधिकतम इस्तेमाल किया जाए। इसी कॉम्प्लेक्स के साथ में डीडीए की एक और जगह है। कोशिश है कि दोनों जगहों को मिलाकर इसे रीडिवेलप किया जाए। अधिकारी के अनुसार इस समय सोसायटी में 336 फ्लैट्स हैं। आरडब्ल्यूए के अनुसार नरेला में जो फ्लैट्स लोगों को देने का प्रस्ताव है उनकी कीमतें अलग-अलग हैं।

DDA की फर्ज़ी स्कीम पर केस

■ **विस, नई दिल्ली :** डीडीए के नाम पर चल रही एक फर्जी हाउसिंग स्कीम का मामला सामने आया है। डीडीए ने इसे लेकर दिल्ली पुलिस के साइबर क्राइम और इकनॉमिक ऑफेंस विंग में शिकायत दर्ज करवाई है। साथ ही डीडीए ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी स्कीम में इनवेस्ट करने से पहले वे सावधानी बरतें।

डीडीए की सभी ऑनलाइन हाउसिंग स्कीम में अप्लाई करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.dda.org.in और www.dda.gov.in का ही इस्तेमाल करें। अन्य वेबसाइट या व्यक्ति यदि इस तरह के दावे करते हैं तो ये फर्जी हो सकते हैं। डीडीए अपनी सभी हाउसिंग स्कीम का ब्योरा भी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर देती है। लोग इसे समय-समय पर चेक कर सकते हैं। डीडीए ने फेक यूआरएल https://DDAflat.org.in/index.php को लेकर शिकायत दर्ज करवाई है।

हिन्दुस्तान

फर्जी विज्ञापन पर शिकायत दर्ज

नई दिल्ली, प्र.सं.। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने फर्जी वेबसाइट यूआरएल बनाकर फ्लैट के विज्ञापन देने पर दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में शिकायत दर्ज कराई है। डीडीए ने लोगों से अपील की है कि लोग इस तरह के फर्जी विज्ञापनों को लेकर सचेत रहे। डीडीए ने कहा कि अगर किसी को डीडीए की वेबसाइट पर जाना है तो वह सिर्फ **www.dda.org.in** या **www.dda.gov.in** पर जाकर ही आवेदन करें।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
FRIDAY, MARCH 24, 2023

Rate Of Legacy Waste Disposal Soared 4 Times In 6 Months: LG

Saxena Visits Landfills, Takes Stock Of Work

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: The rate of legacy waste disposal increased by almost four times between June and December last year, lieutenant governor VK Saxena said on Thursday.

During his visit to the city's three landfill sites, Saxena said that the rate had gone up to nearly 6 lakh metric tonnes per month in December from just 1.4 lakh metric tonnes in June. The height of the garbage mounds at each of the three sites at Ghazipur, Okhla and Bhalswa has also been reduced by 15 metres in just seven months, the LG added.

A statement from the LG's office claimed that the ongoing waste remediation and disposal works were initiated after Saxena's first visit to the Ghazipur garbage mound in May 2022, right after taking over the post.

The LG stated that sufficient infrastructure and arrangements with central government agencies had now been put in place to ensure a disposal rate of 10 lakh MT per month

The LG stated that sufficient infrastructure and arrangements with central government agencies had now been put in place to ensure a disposal rate of about 10 lakh MT per month, and instructed Municipal Corporation of Delhi to achieve this target during the next three months.

Saxena said that 45 lakh MT of legacy inert and C&D waste had been committed to be consumed by National Highways Authority of India and Delhi Development Authority at their construction sites. Similarly, the waste-to-energy power plants, which were opened and upgraded during the last six months, were consuming 6,000 MTs of refuse-derived fuel waste every day. The cement industry is picking up about 15,000 to 20,000 MT of RDF waste every month for use as fuel.

In another development, paper mills situated in Western UP districts like Shamli and Muzaffarnagar have also started lifting nearly 100 MT of RDF waste per day from Delhi.

According to officials, at present, 50 trommelling machines with enhanced capacity are segregating waste at the three landfill sites, up from 25 in June 2022. For the purpose of real-time monitoring of bioremediation of waste and its disposal, control and command centres have been set up at the landfill sites and transportation trucks have been fitted with GPS devices.

दैनिक जागरण नई दिल्ली, 24 मार्च, 2023

डीडीए के बजट में दिख सकती है जी-20 की झलक

G20 बैठक की तैयारियां

संजीव गुप्ता • नई दिल्ली

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के बजट में भी इस बार जी-20 बैठक की झलक देखने को मिल सकती है। यमुना नदी के डूब क्षेत्र का सुंदरीकरण, मिलेनियम डिपो की जमीन पर साबरमती की तर्ज पर रिवरफ्रंट बनाने और उत्तरी दिल्ली के अशोक विहार में वैष्णवी पार्क विकसित करने जैसी योजनाओं को खासतौर पर तव्वजो दी जा सकती है। संभावना जताई जा रही है कि एलजी वीके सक्सेना की अध्यक्षता में 28 मार्च को प्रस्तावित डीडीए की बोर्ड बैठक में वर्ष 2023-24 के लिए लगभग आठ हजार करोड़ रुपये से अधिक के बजट को स्वीकृति मिल सकती है।

बता दें कि दिल्ली की भू-स्वामित्व एजेंसी डीडीए ही राजधानी के विकास की जिम्मेदारी भी संभालता है। ऐसे में जी-20 जैसे अहम आयोजन के मद्देनजर एलजी ने यमुना के पूरे प्रोजेक्ट में डीडीए की भागीदारी सुनिश्चित कर दी है। डीडीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एयरपोर्ट से धौलाकुआं तक सड़क के सुंदरीकरण पर भी लगातार फोकस किया जा रहा है। असिता ईस्ट और बांसेरा प्रोजेक्ट पर भी काम जारी है। मिलेनियम डिपो पर अनूठा खुला म्यूजियम बनाने का काम भी इसी वर्ष शुरू होने की उम्मीद है।

इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परियोजनाएं, जिनके लिए वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में भी राशि का आवंटन किया गया था, में से भी कुछ को इस वर्ष के मध्य तक और कुछ को वर्ष के अंत तक पूरा कर देने का लक्ष्य तय किया गया है।

द्वारका में 560 करोड़ रुपये की लागत से प्रतिष्ठित भारत वंदना पार्क के विकास का काम पहले से ही प्रगति पर है। 80 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली है यह परियोजना

द्वारका सेक्टर-आठ में सीवेज वाटर ड्रेन का निर्माण, ताकि एयरपोर्ट से पानी की निकासी की जा सके। साथ ही बागवानी के लिए ड्रेन वाटर को पुनः उपयोग में लाने के लिए ट्रंक ड्रेन नंबर दो और ट्रंक ड्रेन नंबर पांच का विकास और पुनरुद्धार किया जा सके

इस साल पूरे होने वाले प्रोजेक्ट

- यमुना डूब क्षेत्र का सुंदरीकरण, रिवरफ्रंट बनाने, उत्तरी दिल्ली में वैष्णवी पार्क योजनाएं रहेंगी

28 मार्च को प्रस्तावित बोर्ड बैठक में एलजी दे सकते हैं करोड़ों के बजट को मंजूरी

जेलोरवाला बाग : डिजाइन और बिल्ड माडल पर 1675 ईडब्ल्यूएस आवास इकाइयों का निर्माण

दिल्ली में खेलों को बढ़ावा देने के लिए द्वारका में तीन नए खेल परिसरों, रोहिणी में एक और द्वारका में गोल्फ कोर्स के निर्माण

कालकाजी विस्तार : डिजाइन और बिल्ड माडल पर 3,024 ईडब्ल्यूएस आवास इकाइयों का निर्माण

अनुरक्षित सिटी पार्कों का विकास, उन्नयन, आधुनिकीकरण और रखरखाव के साथ-साथ 787 पार्कों में एसटीपी स्थापित करना

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost
NEW DELHI | FRIDAY, 24 MARCH, 2023 ----------DATED----------

Height of 3 landfills reduced by 15 metres each in 7 mths: L-G

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: Delhi Lt Governor V K Saxena on Thursday asked MCD officials to issue a seven-day termination notice to the contractor responsible for flattening the garbage moulds at the Ghazipur landfill site and warned that a heavy penalty could also be imposed if the pace of work does not improve.

During a visit to the three landfill sites at Ghazipur, Okhla and Bhalswa, Saxena took stock of the progress made in waste disposal since his first visit to the Ghazipur site on May 29, the Raj Niwas said in a statement.

The National Green Tribunal has constituted a high-level monitoring committee with the L-G as its head.

"The L-G expressed satisfaction over the pace of work at Okhla and Bhalswa landfill sites, which are set to achieve the capacity of disposing of 15,000 MT of waste per day (4.5 lakh MT per month)," the statement said.

"However, he expressed displeasure over the slow pace of work at the Ghazipur landfill site and directed MCD officials to issue a seven-day termination notice to the contractor to expedite the work failing which heavy penalty would be imposed and criminal proceedings against the contractor will be initiated for wasting government funds and time," it added.

Addressing officials, the L-G said sufficient infrastructure has been created with assistance from central government agencies and industry to ensure a disposal rate of about 10 lakh MT per month and asked the MCD to achieve this target in the next three months.

The Raj Niwas said the garbage being disposed from the three landfill sites at an average rate of 1.41 lakh MT per month from 2019 till June 2022, went up to about 6 lakh MT per month by December 2022, thereby, increasing the legacy waste disposal by over 400 per cent.

"During the seven months between July 2022 and February 2023, about 30 lakh MT of solid waste have been disposed from the landfill sites, which has resulted in reducing the height of garbage mounds at each of the 3 sites by at least 15 metres in just 7 months," it said.

The L-G said 45 lakh MT of legacy Inert and C&D waste had been committed to being consumed by the National Highways Authority of India and Delhi Development Authority at their construction sites. He said public participation had ensured the lifting of about 1 lakh MT Inert and C&D waste during the last 6 months.

पंजाब केसरी
DELHI

फर्जी वेबसाइटों को लेकर डीडीए ने की ईओडब्ल्यू और साइबर क्राइम सेल में शिकायत

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): कुछ जालसाज दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों को बड़ा चूना लगाने की फिराक में हैं। डीडीए ने स्वयं इसकी जानकारी दी है। डीडीए के संज्ञान में आया है कि कुछ जालसाज प्राधिकरण की हाउसिंग स्कीम के नाम पर फर्जी यूआरएल (https://DDAflat.org.in/index.php) का इस्तेमाल कर जनता को फ्लैट बुक करने के लिए लुभा रहे हैं। डीडीए ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (ईओडब्ल्यू) और साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही प्राधिकरण ने आम लोगों को भी ऐसे फ्रॉड से सचेत किया है। लोगों को आगह करते हुए डीडीए ने कहा कि ऐसे किसी भी फर्जीवाडे से सावधान रहें और इस प्रकार की प्रक्रिया में लिप्त व्यक्तियों और ऐसी योजनाओं से सावधान रहें। डीडीए की सभी आवास योजनाओं के लिए वेबसाइट माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन करें।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPER: अमर उजाला नई दिल्ली | शुक्रवार, 24 मार्च 2023

पेपर मिलों में होगा कचरे का इस्तेमाल

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने तीन लैंडफिल साइटों का लिया जायजा

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली के कचरे का उपयोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पेपर मिलों में किया जाएगा। इसके लिए शामली, मुजफ्फनगर, इटावा सहित दूसरे शहरों के पेपर मिलों ने रोजाना दिल्ली से 100 टन कचरा उठाना शुरू कर दिया है। इससे भलस्वा, गाजीपुर और ओखला की लैंडफिल साइट की ऊंचाई कम होने के साथ ही दूसरे शहरों की औद्योगिक इकाइयों में कचरे का इस्तेमाल किया जा रहा है।

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बृहस्पतिवार को तीनों लैंडफिल साइट का दौरा कर हालात का जायजा लिया। साइट पर पारंपरिक आरडीएफ (रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल) कचरे के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए की गई पहल के तहत कॉरपोरेट समूहों को भी शामिल किया जा रहा है। पहले सीमेंट उद्योग ईंधन के रूप में उपयोग के लिए हर महीने करीब 15,000-20,000 मीट्रिक टन आरडीएफ कचरे को उठा रहा है। इससे पिछले सात महीनों में करीब एक लाख मीट्रिक टन आरडीएफ का स्थायी रूप से निपटान किया गया। राजस्थान की पांच सीमेंट कंपनियां दिल्ली की लैंडफिल साइटों से आरडीएफ उठा रही हैं।

लैंडफिल साइट के निरीक्षण के दौरान अधिकारी को निर्देश देते एलजी। अमर उजाला

पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई मिलों ने रोज 100 टन कचरा उठाना शुरू किया

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 16 फरवरी के आदेश के तहत यमुना की सफाई की तर्ज पर ठोस अपशिष्ट की निगरानी के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। 2019 से जून 2022 के दौरान प्रतिमाह 1.41 लाख मीट्रिक टन की औसत दर से कचरा का निपटान किया गया। पिछले साल दिसंबर तक यह आंकड़ा करीब 400 फीसदी बढ़कर करीब 6 लाख मीट्रिक टन हो गया।

कचरे के ढेर की 15 मीटर ऊंचाई हुई कम

पिछले साल जुलाई से फरवरी के दौरान यानी सात महीनों के दौरान तीनों लैंडफिल साइट से करीब 30 लाख मीट्रिक टन ठोस अपशिष्ट का निपटान किया गया। इससे तीनों साइट पर कचरे के ढेर की ऊंचाई 15 मीटर की कमी आई। एलजी ने अधिकारियों को बताया कि करीब 10 लाख मीट्रिक टन प्रतिमाह की निपटान दर सुनिश्चित करने के लिए एजेंसियों के साथ मिलकर एमसीडी को इस लक्ष्य को तीन महीने में हासिल करने का निर्देश दिया। उपराज्यपाल ने बताया कि एनएचएआई और डीडीए द्वारा अपने निर्माण स्थलों पर 45 लाख मीट्रिक टन पुराने निर्माण एवं विध्वंस(सी एंड डी) कचरे का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया था।

400 एकड़ जमीन को समतल करने के लिए सीएंडडी वेस्ट का होगा इस्तेमाल : एलजी ने बताया कि बदरपुर में करीब 400 एकड़ निचली भूमि को समतल करने के लिए निर्माण एवं विध्वंस कचरे का उपयोग करने की योजना है। फिलहाल दिल्ली में बढ़ी हुई क्षमता वाली मशीनों का उपयोग लैंडफिल साइट पर कचरे को अलग करने के लिए किया जा रहा है। यह देश में सर्वाधिक है। कचरे के जैव-उपचार और उसके निपटान के लिए तीनों लैंडफिल साइट पर नियंत्रण और कमान केंद्र स्थापित किए गए हैं। कचरा उठाने वाले ट्रकों पर जीपीएस लगाए गए हैं।

धीमी रफ्तार पर एलजी ने जताई नाराजगी

एलजी ने ओखला और भलस्वा लैंडफिल साइट पर चल रहे काम की गति पर संतोष व्यक्त किया है। हालांकि, उन्होंने गाजीपुर लैंडफिल साइट पर काम की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए एमसीडी अधिकारियों को काम में तेजी लाने के लिए ठेकेदार को एक हफ्ते का नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। विफल रहने पर भारी जुर्माना लगाने के साथ साथ ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

THE HINDU

DDA cautions public about fake housing website

Press Trust of India
NEW DELHI

The Delhi Development Authority on Thursday cautioned that some fraudulent people were using a fake URL in the name of its housing scheme to lure public. The DDA said it has has taken a serious view in the matter and police complaints have been lodged.